

## खिलाफत आन्दोलन (Khalifat Movement)

(1)

प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। युद्ध काल में भारतीय मुसलमानों से सहयोग लेने के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड तुर्की के विरुद्ध प्रतिक्रिया की नीति नहीं अपनायेगा और न ही तुर्की साम्राज्य को दिवंग-निवृत्त होने देगा। लेकिन अंग्रेज अपने वायदे से मुकर गये। सीबर्स की संधि द्वारा तुर्की साम्राज्य को दिवंग-निवृत्त कर दिया, उसके (तुर्की) कुछ प्रदेशों को स्वतंत्र बना दिया और कुछ को ब्रिटेन तथा फ्रांस के अधीन कर दिया। सुल्तान एक कैदी मात्र रह गया। तुर्की का सुल्तान संसार के मुसलमानों का खलीफा था। उनकी दुर्दशा देख भारतीय मुसलमान निलनिला उठे और अंग्रेजी राज के विरुद्ध गुस्सा उमड़ पड़ा।

मुसलमानों ने अंग्रेजों के नीति के विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन चलाना शुरू किया। मुसलमानों की मांग थी कि 'तुर्की साम्राज्य को खलामत रखा जाए, तुर्की पर कठोर संधि होने न लागू किया जाए एवं तुर्की के खलीफा (सुल्तान) के धार्मिक नेतृत्व को सदा कायम रखा जाए। 24 नवम्बर 1919 को गाँधीजी, जिन्होंने शुरू से ही अपने-आपको खिलाफत आन्दोलन के साथ रखा था के सनापनित्व में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग, मुत्सदा तथा उलेमा ने भी सम्मेलन में भाग लिया। जिस प्रकार से सरकार भारत के मुसलमानों के प्रति अपने वचन को तोड़ रही थी, उसका गाँधीजी ने विरोध किया क्योंकि गाँधीजी ने इसे हिन्दू मुस्लिम श्रमता के नजबूतीकरण तथा राष्ट्रिय आन्दोलन के लिए मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर समझा। गाँधीजी ने हिन्दुओं से मुसलमानों की संकट के समय में सहयोग करने के लिए खिलाफत आन्दोलन में शामिल होने का आग्रह किया। महात्मा गाँधी की सन्मति पर डॉ० अंसापी के नेतृत्व में एक ब्रिचमंडल वागसरान से मिला। ब्रिचमंडल का मुख्यालय वायसरान की मुसलमानों के क्षुब्धाचिन्तकों से आगत कराना था, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला तो जनवरी 1920 में मीराना सरदार वाली ने अपने भाई शौकत अली के साथ अपने भागलों की परकी करके इंग्लैंड गेजा गया। वे भी वहाँ से खलीफा का

जिसके नेता जवाहर लाल नेहरू एवं सुभाष चन्द्र बोस थे। नवम्बर ② में पूर्व  
शीविलन शैल्य से लौटने के बाद जवाहर पंजी बन गए। 1927 में जेल ले डूले  
के बाद सुभाष ने नौजवानों और छात्रों को संगठित करने में सक्रिय भाग  
लिया। वह भी वामपंजी राष्ट्रवादी नेता बन गए। कांग्रेस के बढ़ते हुए वामपंजी  
के प्रभाव को रोकने के लिए भी कमीशन की स्थापना ले पूर्व निश्चिन्त कर दी गई।

**साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज** — 5 नवम्बर, 1927 को वाय-  
सराय लार्ड इरविन ने भारतीय नेताओं से साइमन कमीशन की नियुक्ति की  
सूचना दी और 8 नवम्बर, 1927 को इसकी घोषणा सोरे देश में की गई। घोषणा  
में कहा गया कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक न सार्वभौम राष्ट्रीय  
कमीशन भारत आने वाला है। कमीशन के अध्यक्ष के नाम पर इसे साइमन  
कमीशन कहा गया। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कारण इसे सफेद  
कमीशन (White Commission) का भी नाम दिया गया। इस कमीशन में ब्रिटिश संसद  
के सभी दलों के प्रतिनिधि थे। कमीशन में भारतीयों को इन कारणों से स्थान नहीं दिया  
गया क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी तथा  
भारत में अनेक वर्गों, सम्प्रदायों और लोगों के अस्तित्व के कारण किसी न किसी वर्ग  
की असंतुष्ट कर ही किसी भारतीय को साइमन कमीशन का सदस्य बनना जा सकता  
था। लेकिन ये दोनों तर्क बहाना थे क्योंकि उस समय भी दो भारतीय, लार्ड सिन्हा  
तथा श्री सफलतावाला भी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे।

**साइमन कमीशन के उद्देश्य** — साइमन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य इस  
बात की जाँच करना था कि भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था किस तरह काम कर  
रही थी तथा इस संवेध में रिपोर्ट तैयार करना था कि क्या भारत में उत्तरदायी शासन  
की स्थापना करना वांछनीय है और यदि हाँ तो किस सीमा तक अथवा इस समय  
भारत को जिस मात्रा में उत्तरदायी शासन प्राप्त है, उसे किस सीमा तक विस्तृत, संशोधित  
या प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। कमीशन को यह भी पता लगाना था कि ब्रिटिश  
भारत में शिक्षा की दृष्टि और प्रतिनिधिक संस्थाओं का विकास कितना हुआ था।  
जाँच के बाद उसे यह भी बताना था कि प्राचीन विद्यामंडलों में दूसरा सदन बन  
पाहिए या नहीं।

**साइमन कमीशन का बहिष्कार** — साइमन कमीशन के उद्देश्य तथा इसकी सदस्य  
ता से भारतीयों को बहुत शोक हुआ। उन्होंने इसे अपमानजनक समझा। अतः समस्त  
से सभी ने कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग,  
हिन्दू महासभा और लिवरल फेडरेशन ने एक स्तर से कमीशन का विरोध किया।  
लेकिन सर जॉन साइमन ने भारत में मुस्लिम लीग के एक वर्ग ने कमीशन का स्वागत  
करने का निश्चय किया। साइमन कमीशन भारत में दो बार आया। पहली बार उफरती

मामलों को सुप्रीम कोर्ट में फैलने के लिए शौच के अधिकार होगा। (3)

(vii) केन्द्रीय कार्यकारिणी - भारत की कार्यकारिणी शक्ति सम्राट के पास रहेगी और वह शक्ति गवर्नर जनरल द्वारा सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से प्रयोग की जायेगी परन्तु यह शक्ति कानूनों और संविधान के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी-परिषद होगी जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य दस मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद सब मामलों के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी।

(viii) उच्चतम न्यायालय - भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करने और प्रिन्सिपल को सभी अपीलें बन्द करने का सुझाव दिया गया। उच्चतम न्यायालय संविधान की रक्षा करेगा और प्रांतों में कानूनों का निर्माण करेगा।

(ix) प्रतिरक्षा - प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, प्रधान सेनापति, वायु सेना और जल सेना के सेनापति, जनरल-स्टाफ के अध्यक्ष तथा दो अन्य सेनिक विशेषज्ञों को मिलाकर एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाए। भारतीय सेनाओं के संबंध में सभी नियम और विनियम इस समिति की सिफारिशों के अनुसार बनाए जाएँ। प्रतिरक्षा सम्बन्धी शॉर्ट रजर्व की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा से लेनी पड़ेगी परन्तु भारत पर विदेशी आक्रमण होने या इसकी सम्भावना होने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी को बिना भी धनराशि के रजर्व का अधिकार होगा।

मैहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया - डॉक्टर गकारिया के शब्दों में, यह एक उच्च कोटि की रिपोर्ट थी जिससे राजनीतिक दृष्टिगत का आभास मिलता है। इसका कारण यह था कि इस रिपोर्ट में पहली बार सब राजनीतिक तथा अन्य सम्झौतों पर विचार किया गया और उनका हल तलाश करने का भल किया गया। पहली बार सब दलों ने इन कठिन समस्याओं के सुलझाने में अपना सहयोग दिया। इस रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान की रूप रेखा निश्चित की गई। इस रिपोर्ट की अनेक बातें आधुनिक संविधान में अपना ली गई हैं, अतः यह रिपोर्ट वर्तमान संविधान का प्रारम्भिक क्रम है और यही इस रिपोर्ट की अधिक से अधिक प्रशंसा है।

यद्यपि यह रिपोर्ट अच्छी थी परन्तु तत्कालीन परिस्थिति में बहुत अधिक प्रगतिशील थी, अतः सरकार ने इसकी स्वीकार नहीं किया। जब यह रिपोर्ट विभिन्न दलों की अलग-अलग बैठकों के सामने आई, तो अनेक कठिनाइयों उत्पन्न हो गई। अनेक दलों ने इस पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार करना आरम्भ कर

इस बात पर काफी मतभेद था। मौलाना अबुल कलाम

1928 ई० की भारत वर्ष में पहुँचा और 31 मार्च की रात ६-७-१९२९ तक ठहरा। इसके बाद उली चले। अंग्रेजों की भारत में आजाद और 13 अप्रैल 1929 तक भेजा रहा। दोनों बार भारत का भ्रमण किया, हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का विशाल शिखर जारी हो गया। मुम्बई, बीकानेर, बीकानेर, लखनऊ आदि सभी बड़े-बड़े नगरों में जहाँ की कमीशनर, भारतीय जनता ने उसका पूर्ण हड़ताल, अंग्रेजों, काली गैंगों और साइमन वापस जाओ के नारे लगे। अपने अंततः का प्रदर्शन किया। जब कमीशनर लखनऊ पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने पंजाब के सरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका पहिले लालाजी की प्लाती पर लाला का प्रहार किया। बृह और विहार लालाजी-पार्टी की सख्त न कर सका और कुछ ही दिनों के बाद स्वर्गवासी हो गए। कलकत्ता में शुभाचन्द्र बोस ने इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाए। कलकत्ता का कमीशन विरोधी प्रदर्शन 931 कमजोर रहा।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट: प्रमुख सिफारिशें - मई 1930 में साइमन

कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रति बिली प्रकार की सख्त प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की गई थी और उसमें डोमिनियन स्टेट्स की वर्णन तक नहीं थी। इससे विपरीत जातिगत तथा साम्प्रदायिक मतभेदों-सेवा विस्तार से वर्णन किया गया था जो निम्नलिखित हैं।

(i) उत्तरदायी शासन की अक्षमता - साइमन रिपोर्ट के अनुसार भारत में संसदीय अक्षमता उत्तरदायी शासन का प्रयोग असफल नहीं रहा है।

(ii) संघ शासन की सनाधि तथा प्रान्तीय स्वशासन - 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित संघ शासन अनेक आंतरिक दोषों के कारण असफल रहा है, अतः संघ शासन का तुरन्त अन्त कर देना चाहिए और प्रान्तों में विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को शासन का भार सौंप दिया जाना चाहिए।

(iii) संघ संघ संघ शासन की स्थापना - भारत में लिए एकात्मक शासन संघ संघ संघ नहीं है और निकट भविष्य में भारत के लिए एक संघ संघ संघ की स्थापना की जाए। इस संघ में ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत और राजपूत देवी रियासतें शामिल होंगी।

(iv) साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व - आयोग के अनुसार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व ही प्रणाली निन्दनीय है, किन्तु फिलहाल उससे स्विता प्रकृत विरुद्ध नहीं है। आयोग इस परिणाम पर पहुँचा कि " हम इस विषय पर सर्वसम्मत हैं कि किसी भी प्रांत में मुख्यतः साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व जारी रखना चाहिए। मुख्यतः मतदाताओं को इस विशेष संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।

(v) कमरेक मताधिकार अलगवहारिक - आयोग के अनुसार सर्वसाम्प्रदायिक कमरेक मताधिकार की बात समझना अलगवहारिक है, किन्तु धीरे-धीरे मताधिकार और विधानमंडलों का विस्तार किया जाना चाहिए।

वापस आये। मुहु के बाद सेवरिम लैफिके अनुसार, तुगी साम्राज्य विनाजित कर दिया गया। सुलतान का खविड रूप में मिडर शहरो का कैदी बना दिया गया। अतः स्पष्ट है कि मुहुकास में मुसलमानों को दिने गये खनी वचन भंग कर दिने वाले तथा तुगी को साम्राज्य वादी शीघ्रण का प्रास बना दिया गया।

मुसलमानों की उप दुर्य से दुर्यी एवं निराशा हीर महात्मा गाँधी ने उन्हें सरकार के विरुद्ध असहयोग/खिलाफत आन्दोलन प्रारंभ करने का परामर्श दिया। 28 मई 1920 को खिलाफत समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दो दिन बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाने का निश्चय किया। परिणामस्वरूप 1920 में कलकता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

महात्मा गाँधी को असहयोगी बनने के कारण :- (i) मुहु का परिणाम (ii) आर्थिक दुर्दशा (iii) महामारी (iv) अकाल (v) सरकार का दमन चक्र (vi) सेना में बाधना (vii) दैवनी की नीति (viii) माण्ट-फोर्ड सुधार से अहंता (ix) रॉलट एक्ट, (x) जातिभेद का वाज हला राठ डलारि।

निर्घस :- निर्घसतः खिलाफत आन्दोलन में महात्मा गाँधी का सहयोग मुसलमानों के प्रति एकजुटता, देश में समरसता तथा देश की प्रगति का द्योतक है। हिन्दू-मुसलमन देश की दो औरने अन्तर्गतों के लिए प्रगति का सूचक है। अंग्रेजों की भुटिस नीति पाराशाही हीर वेखहरा बन गया और लैंगरने, गिरने-पड़ने अपने मूल वचन की ओर वापस हो गये।

(निष्कर्ष)

डॉ० राजू मोची  
विभागाध्यक्ष - राजनीति वि०  
डी०के० कॉलेज, दुमराँव  
दिनांक - 14/08/20